MR. DKPUTY CHAIRMAN: No. House is adjourning now.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: Now there are so many things to be spoken about.

, Sir, we have done a lot of progress in the atomic energy field. We Slave done a lot of progress in (space research. We have done a lot of progress in science and technology. But we have to do a lot in the field of transport, railwaySj national highways, all these things.

Last point, Sir, I would like to conclude because I do not want to speak much because my colleague, Smt. Suryakanta Patil is going to raise very pertinent issues of our region. I have left everything to her because we come from the same place.

We would like to build this country. I want to conclude my speech with a quotation from Madam Gan-dhi'g speech;

> "We would like to build this country in such a manner that if India's name is mentioned anywhere or if its citizens go anywhere, there goes with them a new life, a new strength and a new ideology:"

This is what we want tfnis country to be.

With these few lines I conclude my speech,

> The House adjourned for lunch at thirtyone minutes Bast one of the clock.

The Hou&e reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the dock. [The Vice-Chairman (Shrimati Kanak Mulxherjee) in the Chair],

RE. STATEMENT ON ARTICLE 249

SHRI JASWANT SINGH (Rajasthan); Madam, I have to take one minute. We would like to be informed when the statement on Article 249 is likely to be made. The hon. Minister for Parliamentary Affairs is here and he can inform the House. We were given to understand that it would be made at 2.30 p.m. and were informed ttiat a meeting is taking place between the Attorney-General and the Home Minister. We just want to know when that statement is likely to be made.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : जैसा आपको मालूम है, अपोजीशन के साथ बातचीत हो रही है । अभी तो एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस चल रही है । उसके बाद बता देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह (राजस्थान) : कुछ समय का अन्दाजा बता दीजिये ।

श्री सीता राम केसरी : अभी तो बातचीत चल रही है, समय का अन्दाजा क्या बताएं । आपके दल के नेता वहां पर हैं । आपने यहां पर यह प्रश्न उठा दिया ?

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1986—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KANAK MUKHERJEE). Now we will take up further discussion on the Appropriation (No. 4) Bill, 1986. Shrimati Surya Kanta J. Patil.

श्रीमती सूर्यकांता जयवन्तराव पाटील : (महाराष्ट्र) : माननीय उप-सभाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में पहली बार बोलने जा रही हूं । आपने यह जो मौका मुझे प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूं ।

वित्त मंत्री जी ने जो यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करती हूं । आदरणीय वित्त मंत्री जी, आप अपनी भलमन्साहत के लिए सारे

[श्रीमती सूर्यभंता जयवन्तराव पाटील]

देश में प्रसिद्ध हैं । उस बात का आदर रखते हुए कुछ बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रही हूं । बहुत से विभाग हैं जिन पर धन खर्च होना है । बहुत से विभागों पर जो धन वितरित किया गया है उस वितरण व्यवस्था पर मैं नहीं कहना चाहती हूं । लेकिन चन्द बातें हैं जिन बातों से सीधे इस देश के गरीब आदमी का संबंध पड़ता है, जो इस देश का सही मालिक है, जो इस देश का सही मायनों में हिस्सेदार है । उस गरीब किसान का जिन बातों से संबंध है, जिन नीतियों से संबंध है, उन नीतियों पर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । वाटर रिसोर्सेज पर आपने जो 239 करोड़ रुपये की राशि रखी है, यह मेरी समझ में बहुत कम नजर आती है । नेचुरल कैलामिटीज पर जो आपने 400 करोड़ रुपये रखे हैं-नेचुरल कैलामिटीज इस देश के जीवन का एक हिस्सा बनती जा रही है । आये दिन बाढ़ आती है, आये दिन सूखा पड़ता है, आये दिन तूफान उठते हैं, कुछ न कुछ इस देश में घटता ही रहता है और सदैव नेचुरल कैलामिटीज होती हैं । इनमें कुछ हमारे द्वारा पैदा की हुई कैलामिटीज भी होती हैं । इसलिए जो आपने 4 सौ करोड़ रुपये रखे हैं वह मुझे काफी कम नजर आ रहे हैं । इसलिए मंत्री महोदय इस पर जरूर ध्यान देंगे ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है ।

माननीय वित्त मंत्री जी का मैं एक बात के लिये बहुत गहरे दिल से अभिनन्दन करना चाहती हूं, उनको धन्यवाद देना चाहती हूं जो उन्होंने नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो का स्थापना की । नारकोटिक कन्ट्रोल इस देश में बहुत पहले ही आना चाहिए था, इसकी बहुत पहले से ही आवश्यकता थी । इस देश की नयी पीढ़ी को ध्वस्त करने के लिये बाहर शक्तियां जो साजिश कर रही हैं उस साजिश को हमने अभी तक नजर अंदाज किया है । लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद अब मंत्री महोदय ने जो नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो की बात कही है इसके लिये मैं सारे देशवासियों की तरफ से, सारे युवा पीढ़ी की तरफ से उनको धन्यवाद देती हूं ।

महोदया, अब मैं अपने मूल विषय की तरफ आना चाहती हूं । जो बात मैं कहने जा रही हूं यह सारी बात धनराशि के विवरण के सम्बंध में है । धनराशि के वितरण के विवरण को देखने के पश्चात् हमारे दिल में एक कसक है, दुख है और उस दुख की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वह दुख क्या है । मैं हिन्दुस्तान के उस आदमी की बात कर रही हूं जो आदमी इस देश का किसान है । इस देश के 90 प्रतिशत आबादी खेती करने वाले खेतिहरों की है । खुश किस्मती तब होती जब हिन्दुस्तान का किसान प्रमुख उद्योजक कहलाता । लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 90 प्रतिशत हिस्से में रहने वाला यह किसान मजदूर कहलाता है, उद्योजक नहीं । क्योंकि खेतिहरों को, एग्रीकल्चर को हमने उद्योगों का दर्जा नहीं दिया है । आजादी के 35 साल बाद भी इस देश का जो किसान है वह मजदूर कहलाता है, मालिक नहीं, उद्योजक नहीं, कारखानेदार नहीं जब कि इस देश की खेती को इस देश के एग्रीकल्चर को इस देश का प्रमुख उद्योग होना चाहिए । इस तरफ अगर आप कुछ कर सकें तो आपको जरूर करना चाहिए । देश के इस सर्वोच्च सभागृह में किसानों की तरफ, उनके पक्ष में काफी बोला जाता है और काफी कुछ किया भी गया है । हम यह नहीं कहते कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है । सरकार ने बहुत कुछ किया है और देश को हमने काफी आगे लाया है । लेकिन इसके बावजूद मैं फिर से उस किसान की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि किसानों की क्या स्थिति है । एक किसान अपनी फसल उगाता है और 10-11 महीने मेहनत करने के

बाद, मैं उस छोटे किसान की बात कहने जा रही हूं, जिनके खेतों में इरीगेशन नहीं है और अत्यल्प जमीन के मालिक हैं, जिनके खेतों में नहरें नहीं हैं केनाल नहीं है, उन किसानों की बात मैं कह रही हूं । 10 महीने बुवाई के बाद वह हमेशा आसमान की तरफ देखता है कि कब आसमान बरसेगा और कब उसकी जमीन हरीभरी होगी और कब वह अपनी फसल ले जा सकेगा । 10 महीने की मेहनत के बाद फसल कटने को आती है और तब उसकी दीवाली आती है । श्रीमन, मैं आपको कहना चाहता हूं कि दस महीने के बाद भी, दीवाली का मतलब होता है अंधेरा कम होना । लाखों दीप सीमेंट के जंगलों में जलते हैं लेकिन हमारे इन बेचारे किसानों के जो घर में दीप जलता है उसको जलाने के लिये, उसे तेल नहीं मिलता । मैं उस तेल की हमें फिक्र है । करोड़ों लोगों को खिलाने वाला वह किसान अपने घर को खिलाने के काबिल नहीं रह गया है । हमारी प्लानिंग शायद कुछ अन्याय कर रही है ऐसा अगर किसान होने के नाते हमारे दिल में शक पैदा हो तो शायद आप लोग हमें क्षमा करेंगे इस बात पर । हमारे देहात में हमारा किसान तो दीवाली का दीप जलाने से डर रहा है, हिसाब-किताब लगा रहा है कि उसकी आर्थिक अवस्था इतनी क्षीण अवस्था प्राप्त कर चुकी है कि अपनी निजी रोजमर्रा की जरुरतें पूरी नहीं कर पाता है । मुझे कार्ल मार्क्स की बात याद आती है । कार्ल मार्क्स को मैंने थोड़ा पढ़ा है और थोड़ा समझने की कोशिश की है । मैं शायद कुछ ज्यादा तो नहीं समझ पायी हूं लेकिन कार्ल मार्क्स ने कुछ ठीक कहा है, एग्रीकल्चर के बारे में, पूंजीवाद के बारे में समाजवाद के बारे में । "किसी भी देश में पूंजीवाद का जब विकास होने लगता है तो वहां के खेतिहर लोगों को दबा कर ही यह विकास की क्रिया पूरी होती है यानी पूंजीवाद मजबूत तथा शक्तिशाली होता है ।" यह बात कितने बड़े पैमाने पर सच है इस बात का मुझे पता नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही माहौल मुझे नजर आ रहा है ।

श्रीमन, आप थोड़ा सा इस ओर ध्यान दें । आपकी तवज्जो की मैं आशा करती हूं । आज मैं मार्क्स की बात को थोड़ा कुछ अधिक ठीक भी पा रही हूं । मुझे याद आती है, महात्मा गांधी जी की जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सीने में गोलियां झेली और उनके दिल में शायद वह एक सपना था जो उनके साथ दफन हुआ ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं । उसको पूरा करने के लिए काफी कोशिश भी हमने जरूर की है लेकिन आजादी की लड़ाई के समय उन्होंने दो बातों के ऊपर प्राथमिकता दी थी । ग्रामीण विकास, ग्रामीण स्वराज्य तथा कृषि विकास पर । आजादी के बाद हिन्दुस्तान का भविष्य ग्रामीण विकास पर निर्भर होगा, ऐसी उनकी विचार-धारा थी लेकिन अफसोस आज हम उससे कुछ थोड़ा सा हटे हुए नजर आते हैं । आजादी के बाद देहात खाली होते गये । गांवों से लोग शहरों की ओर भागने लगे रोजी-रोटी के लिए । गांधी जी ने कहा था ग्रामों की ओर चलो देहात की ओर चलो और हमारे देहात के किसान भाई देहात के मजदूर भाई सीमेंट के उन जंगलों की ओर भागने लगे । श्रीमन, सीमेंट के जंगलों में उनको घर तो नसीब नहीं हुए फुटपाथ पर झुग्गी-झोंपड़ी उन्होंने बना ली और अपनी जिन्दगी का खासा काटना तय कर लिया । ऐसा उन्होंने क्यों किया ? ऐसा आपको लगता है, क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने यह मजबूरी क्यों स्वीकार की ? क्यों उन्होंने अपने घर और खेत को छोड़कर सीमेंट के जंगलों में रहना पसंद किया कीड़े-मकोड़ों की तरह क्या उनको अपनी जिन्दगी का जीने का अधिकार नहीं था, क्या हम उनको अपना अधिकार दे नहीं पाए । क्या इस पर आप सोचेंगे ? इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना बहुत जरूरी लगता है । इस पर आप जरूर गौर करें । हमारे ग्रामीण भाई, बम्बई कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली के शहरों में फटेहाल पर जीवन बिता रहे हैं । शहरों में हमारा किसान या मजदूर कोई भी अमीर आदमी नहीं बना वह या तो मिल में मजदूरी करता है या सुबह से

[श्रीमती सूर्यकांता जयवन्तराव पाटील]

से पांच बजे तक काम करने वाला बाबू है। तेहांत सुने हो गये ऐसा क्यों हुआ? उन देहातों और बेघर किसानों का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं। इसलिए मैं चुनौती के साथ इस सदन में कहना चाहती हूं। इस सरकार से आपके माध्यम से कि इस बात के लिए सार्व-स्वधति दोषा है। मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय से कहना चाहती हूं कि आपका न्याय समान नहीं है शायद इस देश में। किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने खून पसीने से बनाई हुई वस्तु का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता है। बल्कि उसे जो मिलता है वह निर्धारित करने वाले कितने लोग खेती करते हैं, यह सोचने की बात है। अब हमारी कपास की बात को ही लीजिये। जिस महाराष्ट्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं उस महाराष्ट्र की कपास की बात मैं कहने जा रही हूं। कपड़े के दाम सरकार रोक नहीं सकती है। आज घटिया से घटिया कपड़ा 10-15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बिकता है लेकिन हमारे किसान भाई 21वीं सदी में जाते हुए भी वहीं के वहीं हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से शासन से निवेदन करना चाहती हूं कि ग्रामीण विकास से इस देश का विकास है। आत्मा है, उसको जीवित रखने के लिए आपको किसान के खेतों में पैदा होने वाली चीजों का दाम उत्पादन खर्च पर आधारित देना होगा। जब तक सरकार इस बात को प्राथमिकता नहीं देगी तब तक हम अपने देश को शक्तिशाली नहीं बना पाएंगे। हम हिन्दुस्तान की अर्थ-व्यवस्था का निर्माण यूरोप की नकल करके नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूरोप का सारा विकास वहां की सारी अर्थ-व्यवस्था कम्प्यूटराइजेशन तथा इंडस्ट्रियलाइजेशन पर निर्भर है। हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है कृषि और उस पर अवलम्बित उद्योग। बाकी सारे उद्योग दूसरा स्थान रखते हैं। हर चीज का अपना महत्व है जैसे थाली में रोटी के साथ और भी पूरक पदार्थ हैं लेकिन रोटी के बगैर खाली दाल सब्जी नहीं खा सकते, अचार नहीं खा सकते हैं, ठीक उसी तरह से हिन्दुस्तान को कृषि विकास के सिवाय कैसे रख सकते हैं। बाढ़ और सूखा तो लगता है कि ग्रामीणों के लिए खग्रास ग्रहण है। इस बाढ़ और सूखे पर करोड़ों रुपये व्यय होते हैं। उसका हिसाब सही माने में लगाया जाये तो पता चलेगा कि अनाज की जगह पैसा किस खूबी से चढ़ाया जाता है। क्या बाढ़ और सूखे पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारी नयी तकनीक हम किन लोगों के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं? जो शहरों की चारदीवारी में सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए और उन 70 प्रतिशत लोगों का क्या होगा जो आपकी ओर देख रहे हैं और आस लगाये हुए हैं। आप शहरों के रुख को ग्रामों की तरफ मोड़ दीजिए। महात्मा गांधी का सपना सच हो जायेगा। उठाइये बड़े-बड़े कारखानों को शहरों से, उनका तब तक लाइसेंस रिन्यू मत कीजिए जब तक वे पिछड़े हुए ग्रामीण भागों में अपने कारखाने न लगायें। लेकिन इन सब बातों के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी होगी और बहुत सी बातों को सोचना होगा। आपको प्लानिंग के अन्दर काफी कुछ तब्दीलियां करनी होंगी और वे तब्दीलियां शायद बेसिक होंगी। वे बेसिक तब्दीलियां लाने के लिए सीना भी बहुत बड़ा और जबर्दस्त चाहिए, सीने में चाहिए चाहत, दर्द और दर्द को समझने की तरफ तथा आदत भी होनी चाहिए किसी के दुख को समझने की, इसके इसके लिए कड़े से कड़े कदम उठाने होंगे। जो करोड़ों रुपया बाढ़ और सूखे पर व्यय होता है तो निर्धारित कीजिए कि इस देश के सात लाख गांवों में पक्की सड़कें बनायी जायेंगी, जहां ब्राड गेज की आवश्यकता है वहीं वह आवश्यक प्राथमिकता के साथ बनाई जायेगी। मैं जिस विभाग से संबंधित हूं, महोदया, वहां पिछले 32 साल से हमारी एक ही मांग है। हम मराठवाड़ा विभाग के लोग 1948 में बिना शर्त महाराष्ट्र में शामिल हुए थे। हम लोग ओल्ड निजाम स्टेट से ताल्लुक रखते हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि क्या हमने गलती की शर्त

न रखकर। लेकिन नहीं हम देश को आजादी के साथ-साथ देश को एक साथ भी रखना चाहते हैं उसके लिए हमने चाहे जो त्याग किया होगा और आगे भी जो करना होगा, हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके माने यह यह नहीं होता कि कोई समझदार बच्चा अपने घर की गरीबी को समझता है तो उसको हमेशा के लिए भूखा रखा जाये। सही मां वह होती है जो घर में जो भी रूखा सूखा होता है उसको समान बांटती है, अपने हर बच्चे को उतना ही देती है। जितना एक बच्चे को मिलेगा उतना ही दूसरे बच्चे को भी मिलेगा। यह नहीं कि मराठवाड़ा के बच्चे समझदार हैं तो उनको हम हमेशा के लिए भूखा रखें, उनकी तरफ न देखें और उनसे यह कहा जाता रहे कि हमारे पास पैसा कम है। हम कब तक सुनेंगे ? पैसा नहीं है, हमारे विभाग का पैसा नहीं मिल रहा है ? लेकिन 70-80 करोड़ की आबादी को देखते हुए हमें तो सच नहीं लगता है। आपके हर विभाग में घाटा चल रहा है, इसके माने कि हमारी जो बेसिक मांगे हैं, जो बेसिक अधिकार हैं उनसे आप हमको वंचित रखेंगे ? क्या हमको वह अधिकार नहीं देंगे जो बेसिकली हमको मिलना चाहिए जो कांस्टीट्यूशनली हमको मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा गहरी बात न करते हुए मैं खाली हमारी ब्राड गेज की मांग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वह मांग आज की नहीं है। वित्त मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आज तो नहीं लेकिन आने वाले विन्टर सेशन में जो पूरक मांगे होंगी, सप्लीमेंटरी डिमांड्स होंगी आप उसमें हमारी इस तकलीफ के ऊपर जो हम 32 सालों से कह रहे हैं, उन पर गौर फरमाइयेगा। मराठवाड़ा जो एक पिछड़ा विभाग है उसमें ब्राड गेज हमें शानो-शौकत के लिए नहीं लेकिन विकास का साधन मानकर चाहिए। वहां जब तक ब्राड गेज की सुविधा नहीं देंगे तब तक कोई भी उद्योग उस पिछड़े हुए विभाग में नहीं आयेगा और हम जहां हैं वहीं रहेंगे। इन सौ बीमारियों का एक ही इलाज है, एक ही दवा है कि आप इस देश की आत्मा को जीवित कीजिए, बलशाली कीजिए तब यह हिन्दुस्तान वह हिन्दुस्तान बन जायेगा जहां से कभी सोने का धुआं निकलता था। यह वही धरती है जो आज भी हिन्दुस्तान में सोना उगलती है, जिसने कभी किसी को निराश नहीं किया। इस देश के किसानों ने देश की झोली पटने तक अनाजों से भरी है। खेद है मुझे कि वह किसान अभी भी भिखारी बना दर-दर भटक रहा है। हिन्दुस्तान की आत्मा भटक रही है। उस आत्मा की आवाज को प्यार से, प्रेम से, सौहार्द से सुनना होगा उनकी मेहनत को सही नाप से तौलना होगा चाहे वह कपास हो, मूंगफली हो, चावल हो, गन्ना हो, कोई भी चीज हो उसका सही निर्धारित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य है उत्पादन और उत्पादकता। इस बातों की बुनियाद हैं वह करोड़ों किसान, मजदूर जो देहातों में रहते हैं। यही सब हमारे बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं, लेकिन उन बीस-सूत्री कार्यक्रमों का संचालन करने वाले साहिबान का उन किसानों से तथा गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। यह कार्यक्रम ठीक नहीं चल पा रहा है क्योंकि जिनके माध्यम से यह कार्यक्रम चलता है, वह उस कार्यक्रम का बोरिया-बिस्तर लपेट देना चाहते है, वह चाहते ही नहीं कि इस देश का गरीब आदमी, इस देश का मजदूर आदमी, इस देश का किसान आदमी इस बीस-सूत्री गीता के माध्यम से आगे जाए।

समाजवाद के विरोधी तो हमेशा से रहे हैं। महोदया, समाजवाद को क्यों नहीं हम पूरी तरह से ला पा रहे हैं जब कि समाजवाद की बात तो महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू, हमारी आदरणीया मोहतरमा इन्दिरा जी से लेकर हमारे युवा नेता राजीव जी तक वह बात चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आगे जाने की, मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखती हूं। मुझे मालूम है कि जब-जब समाजवाद को लाने की कोशिश की गई, तब-तब समाजवाद के आड़े में जो लोग आते हैं वह किन लोगों के बीच में फैल कर बैठे हुए हैं, उनका कितना भारी गठन है ? उस गठन को हमें तोड़ना होगा।

[श्रीमती सूर्यकांता जयवन्तराव पाटिल]

सालों से, वर्षों से कोशिश की जा रही है। समाजवाद के घातक शत्रु कौन हैं, उन शत्रुओं को ढूंढना होगा। अगर वह शत्रु हमारे बीच में भी मिलते हैं, वह कहीं भी मिलते हैं, वह चाहे हमारे कितने प्रियजन क्यों न हों, उन शत्रुओं को खत्म करना होगा। तभी तो हम समाजवाद की ओर जा सकेंगे, महोदया। लेकिन बदकिस्मती से हर समय समाजवाद के दुश्मनों की ताकत अधिक लगती है। यह इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम अपने लक्ष्य से कहीं दूर खड़े दिखाई देते हैं।

हमारे हर नेता ने पब्लिक सैक्टर को बढ़ावा देने की बात की है, लेकिन हम पब्लिक सक्टर में पीछे हो रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर हम से आगे जा रहा है। क्यों पब्लिक सैक्टर के हम पीछे पड़ रहे हैं, कभी विचार किया है? पब्लिक सैक्टर का हर उद्योग क्यों ऐसा हो रहा है कि उसमें हमें घाटा ही घाटा मिल रहा है? उस घाटे की तरफ हम कभी देखते नहीं हैं। जब जब बात आती है किसानों की, तब हम कहते हैं कि इस देश का पब्लिक सैक्टर का उद्योग घाटे में चल रहा है। इसलिए हम पूरा पैसा, पूरी पूंजी जुटा नहीं पाते हैं और उसकी वजह से हम आपको न्याय नहीं दे पाते हैं। यह अक्षम्य-सा मुझे लगता है।

आजादी के 35 साल के बाद की पीढ़ी जो 38 साल की होकर आपके सामने पुकार रही है कि यह अन्याय है, यह न्याय नहीं है इस देश के किसानों के प्रति, जो इस देश का सही मायनों में मालिक है। इसलिए मैं आपसे यह गुजारिश करती हूं, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करती हूं कि आप किसानों को कृषि मूल्य जो दे रहे हैं, वह आपको खर्चे के ऊपर आधारित देने होंगे, देहातों का सुधार करना होगा, देहातों की जो प्राथमिक आवश्यकता है, उसको पूरा कीजिये जैसे बिजली, पानी और शिक्षा। किसानों को कर्जे में डुबाने के बजाए उसको मदद कुछ वस्तु के रूप में दी जाए। इसमें पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा, हम यह नहीं कहते कि किसान पैसे का दुरुपयोग नहीं करता है। किसान तो अनपढ़ होते हैं, महोदया, जो सिर्फ बोने और उपजाने का ध्यान रखते हैं, उनको पैसे के हिसाब-किताब से कोई मतलब नहीं होता। वह गलतियां कर सकता है, जरूर गलतियां करते हैं।

आपकी जो मदद है, वह पैसे के रूप में उनको न दें, उनको कुएं खोद कर दें, आधुनिक औजार लेकर दें, उनको सस्ते फर्टिलाइजर उपलब्ध करके दें, तो शायद आपके पैसे का कुछ वह लोग उपयोग कर पायेंगे।

मैं जाते-जाते किसानों की बात के बाद जिस राज्य का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, उस महाराष्ट्र की चंद मसायल के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, महोदया।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कनक मुखर्जी) : अब बस कीजिए।

श्रीमती सूर्यकांता जयवंतराव पाटिल : हमारे कुछ मसायल केन्द्रीय सरकार के पास पेंडिंग हैं। जल अनुसंधान आयोग--मेरा निवेदन है कि हमारे जो प्रोजैक्टस हैं महाराष्ट्र के, 25 बड़े तथा 48 मीडियम प्रोजैक्टस जो केन्द्रीय शासन में केन्द्रीय जल आयोग की मान्यता के लिए 1974 से आज 1986 तक इतने पैमाने पर पेंडिंग पड़े हैं, आप समझ सकते हैं कि 1974 से आया हुआ प्रोजैक्ट अगर वह एक लाख का प्रोजैक्ट होगा, तो आज एक करोड़ का बन गया होगा।

हमारी प्लानिंग कहां से कहां जा रही है? अगर हम किसी प्रोजैक्ट को इतने दिनों पेंडिंग रखते हैं मान्यता के लिए, तो हम खुद घाटे में जाते हैं, किसान तो बाद में घाटे में जाएगा। वह तो पैदा ही घाटे में जाने के लिए हुआ है। उसकी जिंदगी ही मरने के लिए है, तो हमने उनको प्रदान की है। लेकिन हमारे इतने महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट्स जो हम पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं,

हमको अगर सही मायनों में आगे बढ़ना है तो ये प्रोजैक्ट्स आपको मंजूर करने होंगे । काटन मोनोपली हमारा सब से बड़ा प्रश्न है । काटन की महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैदावार है, और जहां से हमारे कई माननीय सदस्य भी इस सदन में बैठे हुए हैं, मैं काटन मोनोपली की बात करना चाहती हूं। महोदया, यह घाटे में जा रही है । 350 करोड़ रुपये का घाटा इस काटन मोनोपली को हुआ है । वह घाटा क्यों हुआ है ? उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, काटन मोनोपली के जरिए जो कपास की खरीदारी होती है और उसके अन्दर से जो केन्द्र का हिस्सा है वह सी०सी०आई० को खरीदना चाहिए । लेकिन यह सी० सी०आई० वह खरीदती नहीं है । अगर उसने 1/3 हिस्सा खरीद लिया तो हमारी काटन मोनोपली कभी भी घाटे में नहीं जायेगी और इससे केन्द्र शासन को हमारे महाराष्ट्र के किसानों के साथ वफादारी करने का मौका मिलेगा । काटन मोनोपली को जीवित रखना आपका धर्म बनता है, आपका कर्त्तव्य बनता है। जो सी०सी०आई० के मार्फत काटन की खरीददारी है जो आपका हिस्सा है उसको खरीदने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए । मैं अपने राज्य की तरफ से आपको विनती करना चाहती हूं । काटन की ही क्यों सारे अनाज की सपोर्ट प्राइस तय करने के लिए मैं आपको कहती हूं । जब कपास की पैदावार हो जाती है तब काटन प्राइस तय करने वाले लोग जागते हैं और सोचते हैं कि कोई न कोई प्राइस डिक्लेयर करनी चाहिए । जब लेट प्राइस डिक्लेयर होनी शुरू हो जाती है तब हमारा गरीब किसान पैसे के धोखे में आकर सेठ साहूकारों को अपना अनाज और अपनी पैदावार बेचनी शुरू कर देता है । अगर हम प्राइस डिक्लेयर लेट नहीं करें तो हमारे देश का किसान खुशहाल नजर आयेगा ।

महोदया, एक आखिरी हिस्सा है मेरी मांग का और वह रेलवे लाइनों के बारे में है । इसके बारे में हमारे सीनियर सदस्य जाधव जी ने तो कहा ही है, मैं भी उन रेल लाइनों का जिक्र करना चाहती हूं । ब्राडगेज की लाइनों के लिए हम पिछले तीस साल से मांग कर रहे हैं । मनमाड-औरंगाबाद परली बैजनाथ मीटरगेज को ब्राडगेज में बदलने के लिए, परभणी पुर्णामुदखेड, मिरजलातूर नैरोगेज टू ब्राडगेज और अहमदनगर-बीड-परली बैजनाथ नई ब्राडगेज रेलवे लाइन । इन सभी रेलवे लाइनों को आप अगर आने वाली सप्लीमेंट्री डिमांडज के अन्दर रखें तो हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करेंगे । आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी । मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को और सारे सदन को देश के किसानों की ओर कहना चाहती हूं। जैसा मैंने अपने भाषण के शुरू में कहा था कि इस देश का किसान सही हकदार है, सही हिस्सेदार है और सही मालिक है, लेकिन आज वह फुटपाथों में, झोंपड़ों में, मिलों में मजदूर के तौर पर दिखाई देता है और फटेहाल में जीता है । हम यह नहीं कहते कि इस देश की बढ़ती हुई तकनीकी से किसानों को कुछ फायदा नहीं होगा । हम शहर विरोधी भी नहीं हैं । हम खुशहाल शहरी भाइयों को देखकर खुशी जरूर मानते हैं, लेकिन भूखे पेट से कितनी खुशहाली व्यक्त की जा सकती है ? खुद भूखे रह कर दूसरों की थालियों को गिनना बहुत कठिन बात है, बहुत टेढ़ी बात है । हमारा खुद का अपना पेट भूखा हो और हम अपने भाइयों की थालियों में डोसा देखें, किसी की थाली में बिरियानी देखें और हमारी थाली में कुछ भी न हो तो यह कुछ थोड़ा सा गलत लगता है । किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शायद वह किसानों के लिए ही कहा होगा । मैं शेर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, शेर है :

"मयस्सर नहीं थी जिनकी नजर,
वो खास आम हो गए हैं आज ।
जवाहरात से बेश-कीमती थे,
कितने कम दाम हो गए हैं आज ।"

और इन शब्दों के साथ अनुपूरक मांगों का मैं समर्थन करते हुए अपने दो शब्द पूरे करती हूं ।

धन्यवाद ।

3.00 P.M.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Let us congratulate her for her very eloquent maiden speech. I am only wondering why maiden speeches argue against the Government but support them. That ttiey should explain.

श्री बो० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : मेडम वाइस चेयरमेन जो एप्रोप्रियेशन बिल हमारे सामने है, इसमें 1318,40,40,000 का टोटल आउट-लेज बताया गया है। लेकिन जो अहम् समस्याएं हमारे देश के सामने हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए जिन डिपार्टमेंटस के लिए जो रकम एप्रोप्रियेशन बिल में बताई गई है, वह बहुत ही नाकाफी है।

[उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।]

महोदय, जो अहम चीजें हमारी हैं, वह हैं--एरोगेशन, एग्रीकल्चर, एनर्जी, रूरल डवलपमेंट, प्रोवीजन फार ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल हाइवे, न्यू रेलवे लाइन, रेमूनरेटिव प्राइसेज फार फारमर्स। यह चीजें देश को शक्तिशाली, देश को मजबूत बनाने के लिए जरूरी हैं और इन तमाम चीजों के लिए काफी रकम रखनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर कोई ज्यादा गुंजाइश इन चीजों के लिए नहीं है ... (व्यवधान) ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Reddy, you may continue tomorrow. We are now taking up the Resolution. Now Mr. Buta Singh to move the statutory resolution.

STATUTORY RESOLUTION IN PURSUANCE OF ARTICLE 249 OF THE CONSTITUTION

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH): Sir, I beg to move the following Re» solution;

That this House do resolve, in. pursuance of Article 249 of the Constitution, that it is necessary in. the national interest that Parliament should, for a period of one year from 12th August, 1986, make laws with respect to the following matters, namely: —

Public Order (but not including the use of any naval, military or air force or any other armed force of tlie Union or of any other forte subject to the control of the Union or of any contingent or unit thereof in aid of the civil power) (Entry I of List H—State List.);

Police (including railway and village police) subject to the provisions of entry 2A of List I (Entry 2 of List H—State List.);

Pfrisons, ieformatories. Borstal institutions and other institutions of a like nature, and persons detained therein, arrangements with other States for the use of prisons and other institutions (Entry 4 of List n—State List.);

Offences against laws with respect to any, of the matters in this List (Entry 64 of List II'—State List);

Jurisdiction and powers of all courts, except the Supreme Court, with respect to any of the matters in this List (Entry 65 of List II—State List.);

Fees in respect of any of the matters in this List, but not including fees taken in any court (Entry 66 of List II—State List.).

Sir, in the context of the anti-national secessionist and terrorist activities in some parts of the country, conccern has been expressed in this House as also outside about the threat posed to the stability, unity and integrity of India and the need to take effective steps to meet the situation. There are also reports about assistance being